भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4978

जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026/2 चैत्र, 1948 (शक) को दिया गया

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

†4978.कैप्टन बृजेश चौटा:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

श्री जगदम्बिका पाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने हाल के वर्षों में लाभप्रदता, अनर्जक आस्तियों में कमी और कारोबार के विस्तार सहित प्रमुख वित्तीय संकेतकों में सुधार दर्शाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या, शाखाओं के नेटवर्क और शाखाओं की संख्या सहित विशेषकर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक तथा दक्षिण कन्नड़ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या और उनके शाखा नेटवर्क का बैंक-वार ब्यौरा क्या है और कुल कारोबार और निवल लाभ कितना दर्ज किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा सशक्तिकरण, पूंजी निवेश, डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना और उन्नत शासन के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) देशभर में वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण और ग्रामीण ऋण पहुंच को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। पिछले चार वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आरआरबी की निम्नलिखित समीक्षाएं आयोजित की गई हैं:

क्र.सं.	**राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर**	**तारीख और स्थान**
1.	राष्ट्रीय स्तर	07.07.2022 को नई दिल्ली में
2.	पूर्वोत्तर आरआरबी	21.07.2023 को अगरतला में
3.	दक्षिणी आरआरबी	04.08.2023 को चेन्नई में
4.	उत्तरी आरआरबी	30.08.2023 को नई दिल्ली में
5.	राष्ट्रीय स्तर	19.08.2024 को नई दिल्ली में
6.	पश्चिमी-मध्य आरआरबी	22.08.2024 को उदयपुर में
7.	पूर्वोत्तर आरआरबी	30.09.2024 को ईटानगर में
8.	दक्षिणी आरआरबी	09.11.2024 को बेंगलुरु में

9.	पूर्वी आरआरबी	29.11.2024 को पटना में
10.	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	16.10.2025 को बेल्लारी में

इसके अलावा, अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) विभिन्न स्तरों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों के साथ आवधिक और नियमित बैठकें आयोजित करता है।

हाल के वर्षों में आरआरबी की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। आरआरबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 7,571 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक समेकित निवल लाभ दर्ज किया, इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6,820 करोड़ रुपये का दूसरा सबसे अधिक निवल लाभ हुआ। वित्तीय वर्ष 2025-26 के नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) में, आरआरबी ने 7,160 करोड़ रुपये *(अनंतिम) का समेकित* निवल लाभ दर्ज किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), जमा राशियों, अग्रिमों, गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए), ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) आदि जैसे प्रमुख वित्तीय मानदंडों में भी लगातार सुधार दर्शाया है। पिछले तीन वर्षों में प्रमुख वित्तीय मापदंडों के संबंध में आरआरबी का कार्यनिष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 26 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 22,207 शाखाओं के साथ 28 आरआरबी प्रचालनरत हैं। शाखाओं की संख्या का आरआरबी-वार ब्यौरा **अनुबंध II** में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एचपीजीबी) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रचालनरत है और कर्नाटक ग्रामीण बैंक (केजीबी) कर्नाटक राज्य में प्रचालनरत है। 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आरआरबी के लिए जिला-वार शाखा नेटवर्क का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध III** और **अनुबंध IV** में दिया गया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) के दौरान हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार और निवल लाभ निम्नानुसार है:

एचपीजीबी (करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल कारोबार**	**निवल लाभ**
1	2022-23	11,112	2.17
2	2023-24	12,327	6.89
3	2024-25	13,616	34.71

स्रोत: नाबार्ड

वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में, एचपीजीबी का कुल कारोबार और निवल लाभ क्रमशः 14,492 करोड़ रुपये और 26.07 करोड़ रुपये *(अनंतिम)* है।

कर्नाटक ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती) (करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल कारोबार**	**निवल लाभ**
1	2022-23	61,202	7.56
2	2023-24	62,422	-174.27
3	2024-25	63,533	-791.31

कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती) (करोड़ रुपये में)			
क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कुल कारोबार**	**निवल लाभ**
1	2022-23	32,450	40.25
2	2023-24	35,383	104.17
3	2024-25	37,912	126.04

स्रोत: नाबार्ड

कर्नाटक के उपर्युक्त दोनों पूर्ववर्ती आरआरबी का समामेलन 01.05.2025 को हुआ था और नई संस्था अब कर्नाटक ग्रामीण बैंक है। वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में, केजीबी का कुल कारोबार और निवल लाभ क्रमशः 1,02,063 करोड़ रुपये और 32 करोड़ रुपये *(अनंतिम)* है।

(घ): सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति लागू की है:

1) आरआरबी के समामेलन का चरणबद्ध कार्यान्वयन:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रचालनात्मक व्यवहार्यता में सुधार करने और बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005-06 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चरणबद्ध संरचनात्मक समेकन की शुरुआत की थी। पहले तीन चरणों (2005-2021) में, मार्च 2021 तक आरआरबी की संख्या 196 से घटाकर 43 कर दी गई थी।

'एक राज्य-एक आरआरबी' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित समामेलन के चौथे चरण में, 01.05.2025 को आरआरबी की संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई।

2) आरआरबी का पुनर्पूंजीकरण: आरआरबी के पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में सुधार के लिए, भारत सरकार ने 10,890 करोड़ रुपये (भारत सरकार के 5,445 करोड़ रुपये के हिस्से सहित) के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आरआरबी में निवेश किया गया था।

3) व्यवहार्यता योजना ढांचे का कार्यान्वयन: आरआरबी को पुनर्पूंजीकरण सहायता की मंजूरी के परिणामस्वरूप, सभी आरआरबी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक स्मार्ट (विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध) मेट्रिक्स के साथ 3 वर्षीय बोर्ड अनुमोदित व्यवहार्यता योजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य **ऋण विस्तार, कारोबार विविधीकरण, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, लागत युक्तीकरण, प्रौद्योगिकी को अपनाने और कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार के माध्यम से निरंतर व्यवहार्यता प्राप्त करना था**

4) डिजिटल बैंकिंग अवसंरचना: सभी आरआरबी ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू किया है और उनमें से अधिकांश अपने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और कॉन्टैक्ट लेस डेबिट कार्ड जैसी डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं।

5) उन्नत अभिशासन: बेहतर अभिशासन के लिए, वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी आरआरबी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति की है। इसके अलावा, प्रायोजक बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए अपने संबंधित आरआरबी को सहायता प्रदान करें।

(ङ): आरआरबी की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, लघु उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए छोटे और सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों, आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण संवितरण के लिए एक वैकल्पिक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। आरआरबी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को लगातार पूरा किया है और अक्सर उससे ज्यादा किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। ये शाखाएं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

सरकार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करती है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जैसी विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के लक्ष्य डीएफएस द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और समय-समय पर उनकी निगरानी की जाती है। इसके अलावा, आरआरबी ने व्यापक वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए 01.07.2025 से 31.10.2025 तक डीएफएस के ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर के संतृप्ति अभियान में भाग लिया है।

*****

अनुबंध I

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के संबंध में 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4978 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रमुख वित्तीय मानकों पर आरआरबी का प्रदर्शन

क्र.सं.	**प्रमुख वित्तीय पैरामीटर**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार** *(अनंतिम)*
1.	कुल जमा (करोड़ रुपये में)	6,08,509	6,59,815	7,13,800	7,33,959
2.	बकाया ऋण (करोड़ रुपये में)	4,14,368	4,71,384	5,26,763	5,65,614
3.	ऋण-जमा अनुपात (सीडी अनुपात) (%)	68.1	71.4	73.8	77.0
4.	सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) (%)	7.2	6.1	5.4	5.6
5.	निवल गैर-निष्पादित आस्ति (एनएनपीए) (%)	3.2	2.4	2.0	2.2
6.	निवल लाभ (करोड़ रुपये में)	4,974	7,571	6,820	7,160
7.	निवल संपत्ति (करोड़ रुपये में)	47,451	56,780	63,927	71,712
8.	पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.4	14.2	14.4	15.0

स्रोत: आरआरबी

अनुबंध II

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के संबंध में 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4978 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	आरआरबी का नाम	शाखाओं की संख्या (31.12.2025 पर)
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	1,351
2	अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक	38
3	असम ग्रामीण बैंक	464
4	बिहार ग्रामीण बैंक	2,101
5	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	627
6	गुजरात ग्रामीण बैंक	745
7	हरियाणा ग्रामीण बैंक	693
8	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	274
9	जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण बैंक	326
10	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	449
11	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	1,750
12	केरल ग्रामीण बैंक	635
13	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	1,319
14	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	752
15	मणिपुर रूरल बैंक	27
16	मेघालय रूरल बैंक	89
17	मिजोरम रूरल बैंक	106
18	नागालैंड रूरल बैंक	14
19	ओडिशा ग्रामीण बैंक	979
20	पुदुचेरी ग्रामा बैं क	48
21	पंजाब ग्रामीण बैंक	470
22	राजस्थान ग्रामीण बैंक	1,596
23	तमिलनाडु ग्रामा बैंक	685
24	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	933
25	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	150
26	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	4,330
27	उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	296
28	पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक	960
कुल		**22,207**

स्रोत: आरआरबी

अनुबंध III

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के संबंध में 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4978 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखाओं की जिला-वार संख्या		
क्र.सं.	**जिला का नाम**	**शाखाओं की संख्या (31.12.2025 पर)**
1	बिलासपुर	14
2	चंबा	39
3	हमीरपुर	25
4	कांगड़ा	52
5	किन्नौर	3
6	कुल्लू	19
7	लाहौल एवं स्पीति	2
8	मंडी	57
9	शिमला	26
10	सिरमौर	9
11	सोलन	14
12	ऊना	14
कुल		**274**

स्रोत: एचपीजीबी

अनुबंध IV

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा" के संबंध में 23.03.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4978 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कर्नाटक ग्रामीण बैंक की शाखाओं की जिला-वार संख्या		
क्र.सं.	**जिला का नाम**	**शाखाओं की संख्या (31.12.2025 पर)**
1	बागलकोट	76
2	बेल्लारी	52
3	बेलगावी	167
4	बेंगलुरु ग्रामीण	19
5	बेंगलुरु दक्षिण	14
6	बेंगलुरु शहरी	51
7	बीदर	51
8	चामराजनगर	26
9	चिक्काबल्लापुर	37
10	चिक्कमगलुरु	52
11	चित्रदुर्ग	84
12	दक्षिण कन्नड़	24
13	दावणगेरे	51
14	धारवाड़	75
15	गडग	61
16	हसन	60
17	हावेरी	77
18	कलबुर्गी	87
19	कोडागु	26
20	कोलार	45
21	कोप्पल	51
22	मांडया	58
23	मैसूरु	95
24	रायचूर	68
25	शिवमोग्गा	42
26	तुमकुरु	67
27	उडुपी	23
28	उत्तर कन्नड़	46
29	विजयनगर	50
30	विजयपुर	79
31	यादगीर	36
कुल		**1,750**

स्रोत: केजीबी